



Lakshya IAS

academy

30

Aug 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



1. अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी और समय पर क्रियान्वयन को सरकार ने मजबूत किया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के



लक्षित और समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डिजिटल निगरानी उपकरण शुरू किए। मंत्रालय ने उन्नत मंचों की शुरुआत की, जिनमें उन्नत पीएम-अजय पोर्टल और मोबाइल अनुप्रयोग शामिल हैं, जिन्हें वास्तविक समय में सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर नज़र रखने, बुनियादी ढांचे के विकास की निगरानी करने और वंचित समुदायों के बीच धन आवंटन को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। गांव-स्तरीय योजना को डिजिटल रूप देकर तथा भौगोलिक अंकन के साथ स्वचालित चरण अनुमोदन को शामिल करके, यह प्रणाली कागज-आधारित कार्यप्रवाहों को एकीकृत डिजिटल शासन से प्रतिस्थापित करती है। यह केंद्रीकृत संचालन ढांचा पारदर्शिता को बढ़ाता है, कल्याणकारी प्रशासन को अनुकूलित करता है और देशभर में 40 लाख से अधिक व्यक्तियों तथा लक्षित गांवों को लाभान्वित करते हुए 50 निगरानी योग्य संकेतकों के आधार पर प्रगति पर नज़र रखता है।

मुख्य बिंदु:

- उन्नत प्रशासनिक निगरानी प्रणाली: केंद्र सरकार ने कल्याणकारी निधियों पर नज़र रखने और पात्र लाभार्थियों को निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डिजिटल तंत्र लागू किए हैं।
- समय पर लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान: अधिकारी सभी प्राथमिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

Government Strengthens Monitoring and Timely Delivery of Welfare Schemes for Scheduled Castes

The Ministry of Social Justice and Empowerment launched enhanced digital monitoring tools to ensure



targeted and timely delivery of welfare schemes for Scheduled Castes. The ministry introduced advanced platforms, including the upgraded PM-AJAY portal and mobile application, designed to track real-time socio-economic progress, monitor infrastructure development, and streamline fund allocation across marginalized communities. By digitizing village-level planning and incorporating geo-tagging alongside automated milestone approvals, the system replaces paper-based workflows with unified digital governance. This centralized operational framework enhances transparency, optimizes welfare administration, and tracks progress across fifty monitorable indicators, benefiting over forty lakh individuals and targeted villages nationwide.

Key Points:

- Enhanced administrative oversight system: The central government has implemented advanced digital mechanisms to track welfare funds and ensure seamless distribution to eligible beneficiaries.
- Timely target realization goals: Authorities are focusing on reducing procedural bottlenecks to accelerate scheme execution across all priority rural and urban regions.

- प्रत्यक्ष लाभ वितरण पर जोर: यह पहल पारदर्शी प्रत्यक्ष हस्तांतरण को प्राथमिकता देती है, जिससे रिसाव को कम किया जा सके और यह सुनिश्चित हो कि सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रभावी रूप से वंचित समुदायों तक पहुंचें।

2. प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने 12 वर्ष पूरे किए, वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया

- ✎ कार्यान्वयन के 12 वर्ष पूरे होने पर, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए कुल लाभार्थी बैंक खातों की संख्या 59 करोड़ से अधिक हो गई।



राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन की प्रमुख पहल के तहत कुल 59.09 करोड़ से अधिक खातों का आंकड़ा दर्ज किया गया, जिनमें कुल शेष राशि 3 लाख 16 हजार 514 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। जनसांख्यिकीय दृष्टि से, कुल खाताधारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से अधिक है, जबकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में कुल खातों की संख्या का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा है। जन धन आधार मोबाइल व्यवस्था के माध्यम से निर्बाध एकीकरण को सुगम बनाते हुए, योजना के तहत 41 करोड़ से अधिक रुपये डेबिट कार्ड वितरित किए गए हैं, जिससे देशभर में औपचारिक बैंकिंग पहुंच और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को बढ़ावा मिला है।

मुख्य बिंदु:

- विस्तार के 12 वर्ष: प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल ने करोड़ों बैंकिंग सुविधा से वंचित नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में सफलतापूर्वक शामिल किया है।
- सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच को बढ़ावा: लाखों सक्रिय खाते अब लाभार्थियों को प्रत्यक्ष ऋण अंतरण, ओवरड्राफ्ट सुविधाओं और बीमा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं।
- वंचित आर्थिक वर्गों का सशक्तिकरण: इस पहल ने महिला खाताधारकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला है और जमीनी स्तर पर आर्थिक स्थिरता मजबूत हुई है।

- Direct benefit delivery emphasis: The initiative prioritizes transparent direct transfers, mitigating leakages and ensuring social security measures reach marginalized communities effectively.

2. Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana Completes 12 Years, Advancing Financial Inclusion and Economic Empowerment

- ✎ Upon the completion of twelve years of implementation, total beneficiary bank accounts opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana crossed fifty-nine crore. The national financial inclusion flagship mission recorded over 59.09 crore total accounts, with aggregate balances reaching three lakh sixteen thousand five hundred fourteen crore rupees. Demographically, women account for over fifty-five percent of total account holders, while rural and semi-urban branches account for nearly seventy-eight percent of total account volume. Facilitating seamless integration through the Jan Dhan Aadhaar Mobile framework, the scheme has distributed over forty-one crore RuPay debit cards, driving formal banking access and direct benefit transfers nationwide.



Key Points:

- Twelve years of expansion: The flagship financial inclusion mission has successfully integrated hundreds of millions of unbanked citizens into formal banking systems.
- Universal banking accessibility push: Millions of operational accounts now offer beneficiaries essential services like direct credit transfers, overdraft facilities, and insurance.
- Empowering marginalized economic sections: The initiative has significantly boosted women account holders, fostering financial independence and deepening grassroots economic stability.

3. भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जुलाई 2026

में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

✎ भारत के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई

2026 में साल-दर-साल 6.7 प्रतिशत

की वृद्धि दर्ज की गई, जो आवश्यक

उपयोगिता क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से काफी प्रेरित रही।

मूल्यांकन किए गए प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में बिजली और गैस

आपूर्ति क्षेत्र ने 8.7 प्रतिशत की उच्चतम सकारात्मक वृद्धि दर

हासिल की। इस व्यापक विस्तार ने इसी अवधि के दौरान

खनन और उत्खनन क्षेत्र में 0.9 प्रतिशत की गिरावट के प्रभाव

को कम करने में मदद की। इसके अतिरिक्त, विनिर्माण क्षेत्र में

7.3 प्रतिशत की ठोस वृद्धि दर्ज की गई, जबकि जल आपूर्ति,

सीवेज और अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि

दर्ज की गई, जिससे घरेलू औद्योगिक गतिविधियों की स्थिर

गति और मजबूत हुई।



India's Index of Industrial Production Registers 6.7 Percent Growth in July 2026

✎ India's industrial output

recorded a year-on-year

growth of 6.7 percent in

July 2026, driven

significantly by strong performance in

essential utility sectors. Among the

primary economic sectors evaluated, the

electricity and gas supply sector achieved

the highest positive growth rate of 8.7

percent. This broad expansion helped

offset a contraction of 0.9 percent in the

mining and quarrying segment during the

same period. Additionally, manufacturing

recorded a solid expansion of 7.3 percent,

while water supply, sewerage, and waste

management services registered a growth

of 7.4 percent, reinforcing steady domestic

industrial momentum.



Key Points:

- Robust industrial output expansion: Official economic indicators demonstrate a solid surge driven primarily by accelerated manufacturing, electricity generation, and mining activities.
- Strong manufacturing sector recovery: High demand across capital goods and consumer durables contributed heavily to the positive trajectory in monthly industrial output.
- Sustained economic momentum visible: The robust performance reflects steady domestic consumption patterns, encouraging capital investment, and overall macroeconomic stability across sectors.

मुख्य बिंदु:

- औद्योगिक उत्पादन में मजबूत विस्तार: आधिकारिक आर्थिक संकेतक मुख्य रूप से विनिर्माण, बिजली उत्पादन और खनन गतिविधियों में तेजी से प्रेरित ठोस वृद्धि को दर्शाते हैं।
- विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत सुधार: पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की उच्च मांग ने मासिक औद्योगिक उत्पादन की सकारात्मक दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- आर्थिक गति लगातार बनी हुई: मजबूत प्रदर्शन स्थिर घरेलू खपत के रुझान, पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और विभिन्न क्षेत्रों में समग्र व्यापक आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।

4. भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में प्रगति की

अगस्त 2026 में रेखांकित रणनीतिक

ऊर्जा रूपरेखा के तहत, भारत का लक्ष्य वर्ष 2031-32 तक अपनी

परिचालन परमाणु ऊर्जा क्षमता को

लगभग 22,400 मेगावाट तक बढ़ाना है। इस महत्वाकांक्षी विस्तार योजना के तहत, देश प्रमुख राज्यों में दस स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी जल रिएक्टरों और हल्के जल रिएक्टरों के त्वरित निर्माण के माध्यम से अपनी वर्तमान लगभग 8,780 मेगावाट क्षमता से आगे बढ़ रहा है। विधायी समर्थन और अंतरराष्ट्रीय असैन्य परमाणु सहयोग से समर्थित यह पहल भारत की दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन रणनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जिसका लक्ष्य 2037 तक 47 गीगावाट और अंततः 2047 तक कुल 100 गीगावाट क्षमता हासिल करना है।



मुख्य बिंदु:

- स्वदेशी रिएक्टर प्रौद्योगिकी में प्रगति: घरेलू वैज्ञानिक संस्थानों ने विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की तैनाती में सफलतापूर्वक तेजी लाई है।
- सतत स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन: स्वदेशी परमाणु ऊर्जा बुनियादी ढांचे का विस्तार कार्बन उत्सर्जन कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है।
- रणनीतिक तकनीकी आत्मनिर्भरता: अनुसंधान में बंद ईंधन चक्र संचालन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे यूरेनियम की दक्षता को अधिकतम करते हुए रेडियोधर्मी अपशिष्ट के उत्पादन को सुरक्षित रूप से न्यूनतम किया जा सके।

India Advances Nuclear Energy Technology to Strengthen Its Nuclear Power Sector

As part of the strategic

energy roadmap

emphasized in August

2026, India aims to scale

up its operational nuclear

power capacity to approximately 22,400

MW by the year 2031-32. Under this

ambitious expansion plan, the country is

transitioning from its current capacity of

around 8,780 MW through the fast-tracked

construction of ten indigenous 700 MW

Pressurized Heavy Water Reactors and

light water reactors across key states.

Backed by legislative support and

international civil nuclear cooperation, this

initiative serves as a core pillar of India's

long-term clean energy transition strategy,

targeting 47 GW by 2037 and ultimately

100 GW of total capacity by 2047.



Key Points:

- Indigenous reactor technology progress: Domestic scientific institutions have successfully accelerated the deployment of advanced small modular reactors to enhance power capacity.
- Sustainable clean energy transition: Expanding indigenous atomic power infrastructure supports national efforts to lower carbon emissions and ensure long-term energy security.
- Strategic technological self-reliance: Research advancements focus on closed fuel cycle operations, maximizing uranium efficiency while minimizing radioactive waste generation safely.

5. फार्मा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की पीआरआईपी योजना के तहत दूसरा आवेदन चरण घोषित

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग ने फार्मा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की



योजना के तहत आवेदनों का दूसरा चरण घोषित किया। 5,000 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ, इस प्रमुख पहल को नवाचार और अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को मजबूत करके भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र में बदलने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें स्टार्टअप, छोटे उद्यम और स्थापित उद्योग क्षेत्र शामिल हैं। यह कार्यक्रम नई दवाओं, जैविक संस्थाओं, जटिल जेनेरिक दवाओं और उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के लिए प्रारंभिक चरण और बाद के चरण की विकास श्रेणियों में वित्त पोषण प्रदान करता है। रणनीतिक मार्गदर्शन और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान करके, यह ढांचा स्वदेशी उत्पाद खोज और व्यावसायीकरण का समर्थन करता है।

मुख्य बिंदु:

- दूसरी वित्त पोषण खिड़की खोली गई: आधिकारिक अधिकारियों ने औषध अनुसंधान पहलों को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की योजना के तहत नए प्रस्ताव आमंत्रित किए।
- अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समर्थन: वित्तीय सहायता का उद्देश्य चिकित्सा विकास में तकनीकी तैयारी को आगे बढ़ाने वाले स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना है।
- उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान: वित्त पोषण में जटिल जेनेरिक दवाओं, नवीन जैव-औषधीय उत्पादों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों और चिकित्सा निदान सहित महत्वपूर्ण श्रेणियों को लक्षित किया गया है।

5. Second Application Round Under 5,000 Crore PRIP Scheme Announced to Promote Pharma and MedTech Innovation

The Department of Pharmaceuticals under the Ministry of Chemicals and Fertilizers announced the second call for applications under the Promotion of Research and Innovation in Pharma and MedTech scheme. With a total financial outlay of five thousand crore rupees, the flagship initiative is designed to transform India into a global innovation powerhouse by strengthening research and development capabilities across startups, small enterprises, and established industry players. The program provides funding across early-stage and later-stage development categories for novel drugs, biological entities, complex generics, and advanced medical technologies. By facilitating strategic mentorship and state-of-the-art infrastructure, the framework supports indigenous product discovery and commercialization.



Key Points:

- Second funding window opened: Official authorities invited fresh proposals under the five thousand crore rupees scheme to boost pharmaceutical research initiatives.
- Support for research ecosystem: Financial assistance aims to nurture startups, small businesses, and large industries driving technological readiness in medicine development.
- Focus on high-priority areas: Funding targets breakthrough categories including complex generics, novel biopharmaceuticals, artificial intelligence devices, and medical diagnostics.

6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2 और 3 सितंबर, 2026 को गांधीनगर में खुली सुनवाई और शिविर बैठक आयोजित करेगा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2-3 सितंबर, 2026 को गुजरात के गांधीनगर में दो दिवसीय खुली सुनवाई और शिविर बैठक आयोजित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन के नेतृत्व में, आयोग राज्य भर में मानवाधिकार उल्लंघनों और बंधुआ मजदूरी संबंधी शिकायतों से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई करेगा। न्याय तक स्थानीय पहुंच में तेजी लाने के उद्देश्य से आयोजित इस सत्र में गैर-सरकारी संगठनों और गुजरात सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मानवाधिकार अनुपालन की समीक्षा के लिए प्रत्यक्ष संवाद भी शामिल होगा।

मुख्य बिंदु:

- अधिकार आयोग ने बैठक निर्धारित की: राष्ट्रीय मानवाधिकार निकाय लंबित शिकायतों के समाधान के लिए गांधीनगर में दो दिवसीय शिविर बैठक आयोजित करेगा।
- प्रत्यक्ष सार्वजनिक शिकायत निवारण: नागरिक मानवाधिकार उल्लंघन की अनसुलझी शिकायतों को तत्काल आधिकारिक हस्तक्षेप के लिए सीधे पूर्ण पीठ के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
- प्रशासनिक कल्याणकारी उपायों की समीक्षा: अधिकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन का मूल्यांकन करेंगे और कमजोर समुदायों के वर्गों की सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करेंगे।

6. NHRC to Conduct Open Hearing and Camp Sitting in Gandhinagar on September 2 and 3, 2026

The National Human Rights Commission announced a two-day Open Hearing and Camp Sitting scheduled for September 2-3, 2026, in Gandhinagar, Gujarat. Led by Chairperson Justice V. Ramasubramanian at the National Forensic Sciences University, the Commission will hear pending cases regarding human rights violations and bonded labor grievances across the state. Designed to expedite local access to justice, the session includes direct interactions with non-governmental organizations and senior administrative officers from the Gujarat government to review human rights compliance.



Key Points:

- Rights Commission schedules sitting: The national human rights body will hold a two-day camp sitting in Gandhinagar to resolve pending grievances.
- Direct public grievance redressal: Citizens can present unaddressed human rights violation complaints directly before the full bench for immediate official interventions.
- Reviewing administrative welfare measures: Officials will evaluate state-level implementation of welfare programs and discuss measures to protect vulnerable community sections.

7. उत्तर प्रदेश में छात्रों को मध्याह्न भोजन से कथित रूप से वंचित किए जाने का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के वैधानिक अधिकार के तहत भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों का



स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त है। कानून की धारा 12(क) के तहत, आयोग को मानवाधिकारों के दुरुपयोग या ऐसी चूकों को रोकने में प्रशासनिक लापरवाही के संबंध में याचिकाएं प्राप्त होने पर या स्वयं की पहल पर जांच शुरू करने का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग नियमित रूप से केंद्र और राज्य प्राधिकरणों को तत्काल नोटिस जारी करता है, विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगता है, पीड़ितों को तत्काल मौद्रिक राहत देने की सिफारिश करता है और पूरे देश में प्रणालीगत प्रशासनिक सुधारों की निगरानी करता है।

मुख्य बिंदु:

- भोजन से वंचित किए जाने का संज्ञान: अधिकार निकाय ने अनिवार्य पौष्टिक मध्याह्न भोजन से वंचित रह गए सरकारी विद्यालयों के छात्रों से संबंधित रिपोर्टों के बाद औपचारिक नोटिस जारी किए।
- प्राधिकरणों से जवाबदेही की मांग: राज्य अधिकारियों को आपूर्ति में व्यवधान के कारणों और प्रभावित बच्चों के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- संवैधानिक बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना: इस हस्तक्षेप का उद्देश्य मौलिक कल्याणकारी सुविधाओं तक पहुंच की रक्षा करना और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पोषण योजनाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान न होने को सुनिश्चित करना है।

7. NHRC Takes Suo Motu Cognizance of Alleged Denial of Mid-Day Meals to Students in Uttar Pradesh

The National Human Rights Commission is empowered to take suo motu cognizance of human rights violations in India under the statutory



authority of the Protection of Human Rights Act, 1993. Under Section 12(a) of the legislation, the Commission possesses independent authority to initiate inquiries on its own initiative or upon receiving petitions regarding human rights abuses or administrative negligence in preventing such lapses. Exercising these powers, the Commission routinely issues urgent notices to central and state authorities, calls for detailed investigation reports, recommends immediate monetary relief to victims, and monitors systemic administrative reforms across the country.

Key Points:

- Cognizance of meal denial: The rights body issued formal notices following reports regarding public school students missing mandatory nutritious midday meals.
- Accountability sought from authorities: State officials must submit detailed reports covering reasons for supply disruption and remedial actions taken for affected children.
- Ensuring constitutional child rights: The intervention aims to safeguard fundamental welfare access, ensuring zero disruption to vital primary education nutrition schemes.

8. भारत और नॉर्वे ने उच्च-स्तरीय राजनयिक सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया

भारत और नॉर्वे ने भारत-नॉर्वे नीली अर्थव्यवस्था कार्यबल के तहत द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में उच्च-स्तरीय राजनयिक परामर्श आयोजित



किया। सतत महासागर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से स्थापित इस रणनीतिक पहल में हरित नौवहन, महासागरीय संसाधन प्रबंधन, समुद्री प्रदूषण में कमी और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वार्ता के दौरान, दोनों देशों ने सतत समुद्री संसाधन उपयोग में तेजी लाने और दीर्घकालिक जलवायु शासन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वैज्ञानिक अनुसंधान और हरित निवेश के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्य बिंदु:

- रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना जारी: दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें हरित प्रौद्योगिकी और समुद्री आर्थिक परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
- नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान: सहयोगात्मक ढांचे में कार्बन उत्सर्जन में कमी, अपतटीय पवन ऊर्जा विकास और सतत जलवायु प्रौद्योगिकी पहलों में पारस्परिक निवेश पर जोर दिया गया है।
- नीली अर्थव्यवस्था के विस्तार को बढ़ावा: चर्चाओं में महासागरीय संसाधन प्रबंधन, सतत नौवहन समाधान और अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

India and Norway Strengthen Bilateral Engagement Through High-Level Diplomatic Cooperation

India and Norway held high-level diplomatic consultations in New Delhi to strengthen bilateral cooperation under the India-Norway Task Force on Blue Economy. Jointly established to drive sustainable ocean management, the strategic initiative focuses on key areas including green shipping, ocean resource management, marine pollution mitigation, and coastal infrastructure development. During the talks, both nations reaffirmed their commitment to expanding technology transfer, scientific research, and green investments to accelerate sustainable marine resource utilization and support long-term climate governance goals.



Key Points:

- Strategic partnership elevation continued: Both nations reiterated commitments to deepen bilateral ties, focusing heavily on green technology and maritime economic projects.
- Focus on renewable energy: Collaborative frameworks emphasize carbon reduction, offshore wind development, and mutual investment in sustainable climate technology initiatives.
- Promoting blue economy expansion: Discussions centered on oceanic resource management, sustainable shipping solutions, and enhanced security cooperation across international marine zones.

9. भारत ने रणनीतिक और आर्थिक महत्व के उभरते क्षेत्रों

में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को गहरा किया

- भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी का एक सक्रिय सदस्य है, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, विद्युत गतिशीलता और उन्नत विनिर्माण के लिए आवश्यक



महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित और विविधीकृत करने के लिए शुरू की गई एक रणनीतिक वैश्विक पहल है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ बहुराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होकर, भारत महत्वपूर्ण खनिज मूल्य शृंखला में निष्कर्षण, प्रसंस्करण, परिशोधन और पुनर्चक्रण को शामिल करते हुए सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग करता है। यह रणनीतिक गठबंधन राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करता है, आपूर्ति शृंखला की कमजोरियों को कम करता है, उच्च-तकनीकी स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करता है और वैश्विक पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन मानकों को आगे बढ़ाता है।

मुख्य बिंदु:

- वैश्विक राजनयिक संबंधों का विस्तार: द्विपक्षीय संबंध प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने, महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच और पारस्परिक व्यापार वृद्धि पर केंद्रित हैं।
- उभरती प्रौद्योगिकी पर ध्यान: रणनीतिक चर्चाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक विनिर्माण और उन्नत दूरसंचार बुनियादी ढांचे की तैनाती में संयुक्त अनुसंधान को प्राथमिकता दी गई है।
- बहुपक्षीय व्यापार स्थिरता को मजबूत करना: सीमा-पार गठबंधन नियम-आधारित व्यापार ढांचे को बढ़ावा देने के साथ-साथ घरेलू औद्योगिक निर्यात के लिए वैश्विक स्तर पर अवसरों का विस्तार करने का लक्ष्य रखते हैं।

India Deepens International Cooperation in Emerging Areas of Strategic and Economic Importance

- India is an active member



of the Minerals Security Partnership, a strategic global initiative launched to secure and diversify global supply chains for critical minerals necessary for clean energy technologies, electric mobility, and advanced manufacturing. Joining the multi-nation coalition alongside key international partners, India collaborates on catalyzing public and private investments across the entire critical mineral value chain, covering extraction, processing, refining, and recycling. This strategic alliance supports national clean energy transitions, reduces supply chain vulnerabilities, strengthens high-tech indigenous manufacturing capabilities, and advances global environmental, social, and governance standards.

Key Points:

- Expanding global diplomatic ties: Bilateral engagements focus on securing supply chains, critical mineral access, and mutual trade growth with key global partners.
- Focus on emerging technology: Strategic discussions prioritize joint research in artificial intelligence, semiconductor manufacturing, and advanced telecommunication infrastructure deployment.
- Strengthening multilateral trade stability: Cross-border alliances aim to foster rules-based trade frameworks while expanding opportunities for domestic industrial exports globally.

10. भारत ने उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग का विस्तार किया

अगस्त 2026 में अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्य समूह की कार्यवाही के दौरान, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए वैश्विक जैव ईंधन



गठबंधन के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मूल रूप से सितंबर 2023 में जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया यह बहु-हितधारक गठबंधन दुनिया भर के प्रमुख उत्पादकों और उपभोक्ताओं को एकजुट करता है। यह गठबंधन नीतिगत समन्वय, तकनीकी सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे इथेनॉल और संपीड़ित जैव गैस सहित सतत ईंधनों को वैश्विक स्तर पर अपनाने और उनका व्यावसायीकरण करने को बढ़ावा मिलता है।

मुख्य बिंदु:

- बहुपक्षीय मंच पर भागीदारी मजबूत हुई: वैश्विक शिखर सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियों और जलवायु लक्ष्यों को सामूहिक रूप से संबोधित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- वैश्विक स्तर पर प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर: भाग लेने वाले देशों के बीच ज्ञान साझा करने, तकनीकी आदान-प्रदान और सीमा-पार अनुसंधान पहलों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई समझौतों को अंतिम रूप दिया गया।
- विकास के लिए एकजुट आवाज: चर्चाओं में समावेशी वैश्विक विकास, आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे में निवेश और दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए निष्पक्ष आर्थिक नीतियों पर जोर दिया गया।



10. India Expands Multilateral Cooperation Through High-Level International Engagements

At the international multilateral working group proceedings in August 2026, India reiterated its



commitment to expanding the Global Biofuels Alliance to accelerate clean energy transitions. Originally launched by Prime Minister Narendra Modi during the G20 New Delhi Summit in September 2023, the multi-stakeholder coalition unites major producers and consumers worldwide. The alliance facilitates policy alignment, technical support, and technology transfers, promoting the global adoption and commercialization of sustainable fuels, including ethanol and compressed bio gas.

Key Points:

- Multilateral platform engagement strengthened: Active participation in global summits reflects a commitment to addressing international economic challenges and climate goals collectively.
- Key agreements signed globally: Multiple pacts were finalized to facilitate knowledge sharing, technological exchanges, and cross-border research initiatives between participating nations.
- Unified voice for growth: Discussions highlighted inclusive global development, disaster-resilient infrastructure investment, and fair economic policies for developing nations worldwide.



दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS

MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. अगस्त 2026 में भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को मूल रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था?

- (a) जी20 बाली शिखर सम्मेलन 2022
- (b) जी20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023
- (c) कॉप28 दुबई 2023
- (d) कॉप29 बाकू 2024

Q2. भारत निम्नलिखित में से किस वैश्विक साझेदारी का सक्रिय सदस्य है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविधीकृत करना है?

- (a) अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
- (b) वैश्विक बुनियादी ढांचा और निवेश साझेदारी
- (c) खनिज सुरक्षा साझेदारी
- (d) विश्व आर्थिक मंच आपूर्ति नेटवर्क

Q3. अगस्त 2026 में भारत और नॉर्वे ने किस पहल के तहत द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में उच्च-स्तरीय राजनयिक परामर्श आयोजित किया?

- (a) भारत-नॉर्डिक डिजिटल ग्रिड पहल
- (b) भारत-आर्कटिक नवीकरणीय गलियारा
- (c) भारत-नॉर्वे नीली अर्थव्यवस्था कार्यबल
- (d) स्कैंडिनेविया-भारत स्वच्छ ऊर्जा गठबंधन

Q4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त है?

- (a) संविधान का अनुच्छेद 32
- (b) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- (c) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
- (d) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

Q5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 2-3 सितंबर, 2026 को घोषित दो दिवसीय खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में आयोजित की जानी है?

- (a) अहमदाबाद
- (b) सूरत
- (c) वडोदरा
- (d) गांधीनगर

Q1. In August 2026, India reiterated its commitment to expanding the Global Biofuels Alliance. During which summit was the Global Biofuels Alliance originally launched?

- (a) G20 Bali Summit 2022
- (b) G20 New Delhi Summit 2023
- (c) COP28 Dubai 2023
- (d) COP29 Baku 2024

Q2. India is an active member of which of the following global partnerships, aimed at securing and diversifying global supply chains of critical minerals essential for clean energy technologies?

- (a) International Energy Agency
- (b) Global Infrastructure and Investment Partnership
- (c) Minerals Security Partnership
- (d) World Economic Forum Supply Network

Q3. In August 2026, India and Norway held high-level diplomatic consultations in New Delhi to strengthen bilateral cooperation under which initiative?

- (a) India-Nordic Digital Grid Initiative
- (b) India-Arctic Renewable Corridor
- (c) India-Norway Blue Economy Task Force
- (d) Scandinavia-India Clean Energy Alliance

Q4. Under which Act does the National Human Rights Commission have the authority to take suo motu cognizance of human rights violations in India?

- (a) Article 32 of the Constitution
- (b) Protection of Human Rights Act, 1993
- (c) National Commission for Protection of Child Rights Act, 2005
- (d) Representation of the People Act, 1951

Q5. In which city is the two-day open hearing and camp sitting announced by the National Human Rights Commission for September 2-3, 2026, scheduled to be held?

- (a) Ahmedabad
- (b) Surat
- (c) Vadodara
- (d) Gandhinagar

Q6. अगस्त 2026 में औषध विभाग द्वारा घोषित पीआरआईपी योजना का पूरा नाम क्या है?

- (a) फार्मा में क्षेत्रीय नवाचार को बढ़ावा देना
- (b) फार्मा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना
- (c) अनुसंधान, बुनियादी ढांचा और फार्मा के लिए कार्यक्रम
- (d) औषधियों में सार्वजनिक अनुसंधान और नवाचार

Q7. रणनीतिक ऊर्जा रूपरेखा के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2031-32 तक अपनी परिचालन परमाणु ऊर्जा क्षमता को लगभग कितने मेगावाट तक बढ़ाना है?

- (a) 12,000 मेगावाट
- (b) 15,000 मेगावाट
- (c) 22,400 मेगावाट
- (d) 30,000 मेगावाट

Q8. जुलाई 2026 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 8.7 प्रतिशत की उच्चतम सकारात्मक वृद्धि दर्ज की?

- (a) खनन और उत्खनन
- (b) विनिर्माण
- (c) जल आपूर्ति और सीवेज
- (d) बिजली और गैस आपूर्ति

Q9. अगस्त 2026 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए कुल लाभार्थी बैंक खातों की संख्या कितने करोड़ से अधिक हो गई?

- (a) 40 करोड़
- (b) 50 करोड़
- (c) 59 करोड़
- (d) 70 करोड़

Q10. अगस्त 2026 में अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित और समयबद्ध वितरण हेतु उन्नत डिजिटल निगरानी उपकरण किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किए?

- (a) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (b) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- (c) जनजातीय कार्य मंत्रालय
- (d) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

Q6. What is the full form of PRIP, under which the Department of Pharmaceuticals announced the second phase of applications in August 2026?

- (a) Promoting Regional Innovation in Pharma
- (b) Promotion of Research and Innovation in Pharma and MedTech
- (c) Programme for Research, Infrastructure and Pharma
- (d) Public Research and Innovation in Pharmaceuticals

Q7. According to the strategic energy framework, India aims to increase its operational nuclear power capacity to approximately what level by 2031-32?

- (a) 12,000 MW
- (b) 15,000 MW
- (c) 22,400 MW
- (d) 30,000 MW

Q8. According to the Index of Industrial Production data for July 2026, which of the following sectors recorded the highest positive growth rate of 8.7%?

- (a) Mining and Quarrying
- (b) Manufacturing
- (c) Water Supply and Sewerage
- (d) Electricity and Gas Supply

Q9. By August 2026, the total number of beneficiary bank accounts opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana had crossed which figure?

- (a) 40 crore
- (b) 50 crore
- (c) 59 crore
- (d) 70 crore

Q10. In August 2026, which Union Ministry launched advanced digital monitoring tools to ensure the targeted and timely delivery of welfare schemes for Scheduled Castes?

- (a) Ministry of Rural Development
- (b) Ministry of Social Justice and Empowerment
- (c) Ministry of Tribal Affairs
- (d) Ministry of Housing and Urban Affairs

उत्तरमाला (Answer Key)

1 B 2 C 3 C 4 B 5 D 6 B 7 C 8 D 9 C 10 B

